

# श्री नीतीश कुमार

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

के कर-कमलों द्वारा



₹328 करोड़ 52 लाख की लागत से विद्युत संरचना सुद्रढ़ीकरण कार्य के तहत पटना शहरी क्षेत्र में बिजली के तारों को चरणबद्ध रूप से भूमिगत करने की परियोजना

₹59 करोड़ 68 लाख की लागत से सभ्यता द्वार को संपर्कता तथा पटना हाट एवं पार्किंग के निर्माण कार्य

₹30 करोड 02 लाख की लागत से पटना में अवस्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावासों के जीर्णोद्धार

₹387 करोड 40 लाख की लागत से दीघा से गांधी मैदान के बीच जे. पी. गंगा पथ के दोनों तरफ लगभग ७ कि.मी. "जे. पी. गंगा पथ समग्र उद्यान" (फेज-१) परियोजना के निर्माण कार्य

₹196 करोड 80 लाख की लागत से पटेल गोलंबर से अटल पथ तक सरपेंटाइन नाले पर भुमिगत नाले सहित फोरलेन सड़क के निर्माण कार्ये

₹52 करोड़ 28 लाख की लागत से मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन ४- लेन सडक को जे, पी.गंगा पथ से जोडने हेतु संपर्क पथ का निर्माण कार्य

(का

## शिलान्यास/ कार्यारंभ •

विशिष्ट अतिथि

श्री समाट चौधरी

माननीय उप मुख्यमंत्री,बिहार

श्री विजय कुमार सिन्हा

माननीय उप मुख्यमंत्री,बिहार

गरिमामयी उपस्थिति

श्री नितिन नवीन

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव

माननीय मंत्री. ऊर्जा विभाग

श्री सुनील कुमार माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग

श्री जिवेश कुमार

श्री राजू कुमार सिंह माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना के सभी माननीय सांसद. सभी माननीय सदस्य. बिहार विधानमंडल एवं अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण







श्री विजय कुमार चौधरी

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग

जे.पी. गंगा पथ के सौंदर्यीकरण से शहर सुन्दर बनेगा तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पटना हाट के विकास से स्थानीय उत्पादों के लिए एक नया बाजार मिलेगा। नेहरू पथ की जे.पी. गंगापथ से सीधी संपर्कता यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी। बिजली के तारों के भूमिगत होने से सुरक्षा तथा शहर की सुन्दरता बढ़ेगी। छात्रावासों के जीर्णोद्धार से छात्रों को सुविधा होगी।

दिनांकः २४ अगस्त, २०२५ | 🎗 स्थानः पटना | 🕓 समयः ३:०० बजे अपराहन

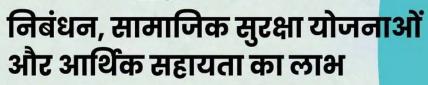




गिग कामगारों को मिला अधिकार बिहार सरकार ने किए सपने साकार

बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार अधिनियम-२०२५

बिहार सरकार के द्वारा गिग कामगारों (जैसे डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर आदि) को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए ऐतिहासिक कदम





दुर्घटना से मृत्यु पर परिजनों को

₹4 लाख

का मुआवजा



अस्पताल में भर्ती पर ₹5,400 से

₹16,000

तक की सहायता



विकलांगता पर ₹74,000 से

₹2.5 लाख

तक का मुआवजा



गर्भावस्था व प्रसव पर महिला कामगारों को

90 दिनो

का मातृत्व लाभ

### असहाय नहीं, अब सशक्त होंगे गिग कामगार



इस अधिनियम के तहत एक विशेष कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा

#### पंजीकरण की अनिवार्यता

सभी गिग कंपनियों को 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा

#### यूनिक आईडी की व्यवस्था

गिग कामगारों को यूनिक आईडी दी जायेगी, जिससे वे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 296 5656 पर संपर्क करें

जन-जन के सपने हो रहे साकार, रफ़्तार पकड़ चुका है बिहार









# बस रहा अपना घर-संसार

# 4,18,394 शहरी एवं 49,03,689 ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास के लिए प्रदान की जा रही है वित्तीय सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

- 2,64,604 घर स्वीकृत
- 1,58,556 घरों का अभी तक निर्माण पूरा एवं शेष का तेजी से निर्माण जारी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0)

•1,53,790 घर स्वीकृत

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- 49,03,689 घर स्वीकृत
- 38,54,489 घरों का अभी तक निर्माण पूरा एवं शेष का तेजी से निर्माण जारी





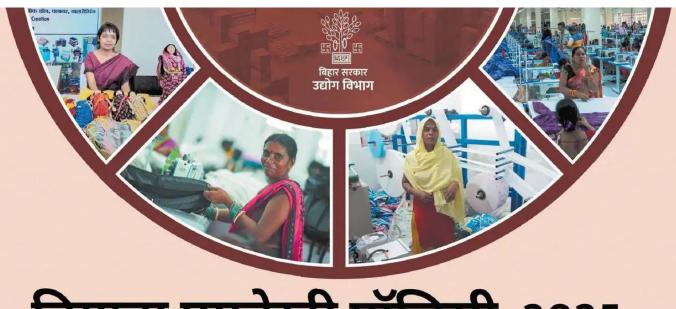




कुल **₹59,377 करोड़ 46 लाख** की लागत से बिहार वासियों के घरों का निर्माण







# बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी, 2025

**BIADA AMNESTY POLICY, 2025** 

बंद उद्योगों को फिर से चालू करने के लिए नया अवसर

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) ने औद्योगिक विकास को नई दिशा देने हेतु "BIADA एमनेस्टी पॉलिसी, 2025" जारी की है। इसका उद्देश्य रद्द किए गए औद्योगिक प्लॉटों पर चल रहे विवादों को सुलझाना. बंद/आंशिक-क्रियाशील इकाइयों को पुनर्जीवित करना तथा बिहार में औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

### नीति की प्रमुख बातें

यह नीति एकमुश्त (One Time) अवसर है, जिसका लाभ 31 दिसम्बर 2025 तक लिया जा सकता है

यह नीति उन सभी आवंटियों के लिए लागू होगी जो स्वेच्छा से इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं

सभी लाभुकों को नए उद्यमियों की तरह उद्योग स्थापित/ पुनर्जीवित करने का अवसर मिलेगा

उद्यमी योजनांतर्गत लाभुक खुद उद्यम चला सकते हैं अथवा उत्पाद में परिवर्तन/ट्रांसफर कर सकते हैं

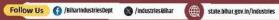
### मुख्य प्रावधान

- 💇 पात्रता: सभी रद्द इकाइयाँ (सिवाय उन मामलों के जहाँ तीसरे पक्ष को भूमि आवंटित की जा चुकी है)।
- 👽 आवेदन प्रक्रियाः इकाइयाँ शपथ पत्र, आवश्यक दस्तावेज़ और शुल्क के साथ ऑनलाइन/ऑफ़लाइन आवेदन करेंगी।
- BIADA 3 कार्य दिवस में सैद्धांतिक स्वीकृति देगा।
- 😻 इसके बाद आवेदक को लंबित न्यायालय मामलों को वापस लेना होगा तथा BIADA के शुल्क को भरना होगा।
- अावेदक की सभी औपचारिकताएँ पूरी होने पर BIADA द्वारा 7 कार्य दिवस में अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।

### शुल्क एवं चार्जेज़

प्रशासनिक शुल्कः इकाई को भुखण्ड दर का 1 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कू देना होगा

रफ़्तार पकड़ चुका है बिहार हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार



# पीएम ने दिया नया लक्ष्य, कहा – अगला कदम अंतरिक्ष अन्वेषण

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर विज्ञानियों से कहा, इसके लिए करें तैयारी

चंद्रमा, मंगल तक पहुंच गए, अब गहरे अंतरिक्ष में झांकना है, जहां छिपे हैं रहस्य

नई दिल्ली, प्रेट्ट: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिनवार को विज्ञानियों को नया लक्ष्य देते हुए कहा कि अगला कदम गहन अंतरिक्ष का अन्वेषण करना है। प्रधानमंत्री ने विज्ञानियों से गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन की तैयारी करने का आग्रह किया ताकि मानवता के भिक्ष्य को उजागर करने वाले रहस्यों को समझा जा सके। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वीडियो संबोधन में पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत 'अंतरिक्षयात्री पूल' तैयार कर रहा है। उन्होंने युवाओं को इस पूल या समूह में शामिल होने के लिए आमात्रत किया।

गौरतलब है कि 2023 में 23 अगस्त को ही चंद्रयान-3 मिशन के तहत भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल साफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है।

पीएम मोदी ने कहा, हम चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गए हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में झांकना है, जहां मानवता के भविष्य के लिए लाभकारी कई रहस्य छिपे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करना अब भारत



नरेन्द्र मोदी।

एएनआइ

और उसके वैज्ञानिकों का स्वाभाविक गुण बन गया है। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के उद्यमियों से यह भी पूछा कि क्या अगले पांच वर्षों में पांच स्टार्टअप यूनिकार्न बन सकते हैं। तांकि भारत अगले पांच वर्षों में हर साल 50 राकेट प्रक्षेपित कर सके।

पीएम ने कहा कि तीन दिन पहले ही उनकी मुलाकात ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से हुई थी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। शुभांशु ने आइएसएस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर भारतीय को गौरवान्वित किया।

इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हम उस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाते हैं जब चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी छुव को छुआ। उस समय हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया। मैं इसरो के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई देता हं।

### अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारे देश के लिए स्वर्णिम समय : शुभांशु

नई दिल्ली, एएनआइ: अंतरिक्षयात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा कि वर्तमान समय अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के लिए 'स्वर्णिम काल' है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के कार्यक्रम में कहा कि पूरी दुनिया भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। शुभाशु ने नेहरू तारामंडल में आर्यभट्ट गैलरी का उदघाटन भी किया।

इसरो अध्यक्ष ने पीएम मोदी को दिया चंद्रवान ३ की सफलता का श्रेय : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंघान संगठन (इसरो) के प्रमुख वी , नारायणन ने चंद्रयान ३ मिशन की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और नेतृत्व को दिया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मुख्य समारोह में इसरो अध्यक्ष ने कहा. २३ अगस्त २०२३ ऐतिहासिक दिन था। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 की सफलतापुर्वक लैंडिंग कराई । हम ऐसा करने वाले एकमात्र देश बन गए। भारत के प्रधानमंत्री दुरदर्शी हैं। उन्होंने कहा, हम चंद्रयान-४ मिशन शुरू करने जा रहे हैं। हम वीनस आर्बिटर मिशन शुरू करने जा रहे हैं। हम 2035 तक बीएएस (भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन) नामक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने जा रहे हैं। इसका पहला माइयुल २०२८ तक प्रक्षेपित किया जाएगा।

### अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है भारत

भारत राकेट और अर्थ इमेजिंग से लेकर अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन तक में वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने 1975 में अपने पहले प्रक्षेपण के बाद से 80 से ज्यादा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित कर चुका है। आइए नजर डालते हैं भारत की खास उपलब्धियों पर....



अंतरिक्ष में भारत की धमक । प्रतीकात्मक

### चंद्रमा पर पानी के सुबूत दिए

इसरों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक चंद्रयान का प्रक्षेपण है, जिसने चंद्रमा पर पानी के प्रमाण प्रदान किए। चंद्रयान—1 मिशन ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पहला वैज्ञानिक प्रमाण दिया था, जिसके बाद 2009 में नासा ने भी इसकी पुष्टि की थी। इसके साथ ही, जीएसएलवी (एमके 3) के माध्यम से भारी पेलोड उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उदाए हैं, जिसमें एक स्ववेशी क्रायोजेनिक इंजन शामिल है।

### भारत का अंतरिक्ष बेड़ा अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित

भारत का अंतरिक्ष बेड़ा अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इसरो वर्तमान में इनसैट और जीसैट शृखला के संचार उपग्रहों, भू–अवलोकन उपग्रहों और आइआरएनएसएस शृंखला के नेविगेशन उपग्रहों का संचालन कर रहा है। भारत के पास टीईएस और कार्टोसैट जैसे डाइब्रिड उपग्रहों का बेड़ा है, जो सैन्य और नागरिक दोनों तरह के उपयोग के लिए कार्य करते हैं। अपना नेविगेशन उपग्रह भी है, जो सटीक लोकेशन प्रदान करता है।

### रूसी रिकार्ड तोड़ दुनिया को चौंकाया

2017 में, भारत ने एक ही राकेट से 104 नैनो उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित कर एक नया विश्व रिकार्ड स्थापित किया। यह उपलब्धि न केवल रूस के रिकार्ड को तोड़ने में सफल रही, बल्कि भारत को उभरते निजी बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित किया।

### विदेशी निजी कंपनियों को भी भारत दे रहा है चुनौती

भारत केवल देशों के साथ ही प्रतिस्पर्धा में नहीं है, बल्कि यह स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियों को भी चुनौती दे रहा है। स्पेसएक्स ने दोबारा इस्तेमाल के योग्य प्रक्षेपण यान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। इसरों ने हाल ही में इस क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की है।

### किफायती मिशनों ने दुनिया में बजाया डंका

इसरो द्वारा एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में उपग्रह प्रक्षेपित करने से इसने तकनीकी प्रगति पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। भारत ने 7 .5 करोड़ डालर की लागत से मंगल आर्थिटर मिशन भी पूरा किया, जो नासा के मावेन मंगल मिशन के बजट का केवल दसवां हिस्सा था।

### आगामी मिशन

आगामी मिशनों की बात करें तो 2027 में गगनयान और एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना के साथ भारत की आकांक्षाएं अब पृथ्वी की कक्षा से आगे बढ़ रही हैं। उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरग्रहीय अन्वेषण में इसरों के निरंतर नवाचार भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अहम भागीदार बना रहे हैं।

# नसबंदी के बाद ही छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते

कुत्तों को पकड़ कर डाग शेल्टर में रखने के 11 अगस्त के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने किया संशोधन आक्रामक और रैबीज संक्रमित कुत्तों को पकड़ने के बाद नहीं छोड़ा जाएगा, सभी राज्यों को नोटिस जारी



#### जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सप्रीम कोर्ट ने आवारा कर्तों को पकड़ कर डाग शेल्टर में रखने के अपने 11 अगस्त के आदेश में शुक्रवार को संशोधन कर दिया। कहा कि आवारा कत्तों को पकड कर उनका बंध्याकरण व टीकाकरण करने के बाद उन्हें छोडा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आक्रामक और रैबीज संक्रमित कुत्ते पकड़ने के बाद छोड़े नहीं जाएंगे। यहां तक कि उन्हें डाग शेल्टर में भी अलग रखा जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और पनवी अंजारिया की पीठ ने यह भी आदेश दिया है कि नगर निकाय तत्काल प्रभाव से प्रत्येक वार्ड में आवारा कतों को भोजन कराने के लिए एक निश्चित स्थान (फीडिंग प्वाइंट) बनाएगा। कोई भी संस्था या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतों को सड़क पर खाना नहीं खिलाएगा और जो व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानुन के मताबिक कार्रवाई होगी।

पीठ ने कहा है कि 11 अगस्त का आदेश यथावत लागू रहेगा। बस उसमें इतना संशोधन है कि पकड़े गए कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण करने के बाद रैबीज संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को छोड़कर बाकी को उसी जगह वापस लाकर छोड़ा जाएगा। दूसरा संशोधन यह है कि पहला आदेश एनसीआर के लिए था। अब यह परे देश में लाग होगा।

सड़कों पर कुत्तों को कोई खाना नहीं खिलाएगा, ऐसा करने पर कार्रवाई होगी



नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट परिसर में शुक्रवार को घुमता आवारा कृता।

#### ाम काट पारसर म शुक्रवार का यूमता आवारा कुता।

### फीडिंग प्वाइंट के पास लगाया जाएगा नोटिस बोर्ड

नगर निकायों की जिम्मेदारी होगी कि वे कुतों के लिए फीडिंग प्वाइट बनाए। उसके पास नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर लिखा होगा कि आवारा कुतों को सिर्फ इसी जगह खाना खिलाया जा सकता है। किसी भी हालात में कुतों को सड़क पर भोजन देने की इजाजत नहीं होगी। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंधन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश इसलिए जारी किया जा रहा है, क्योंकि कुतों के हमले की घटनाएं उन्हें अनियमित तौर पर सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर भोजन कराने के कारण घटती हैं। यह प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस कारण गलियों व सड़कों पर टहलने वालों को बड़ी परेशानी होती है।

कोर्ट ने आठ सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। आठ सप्ताह बाद फिर सनवाई होगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि बड़े पैमाने पर नसबंदी से आवारा कुतों की तेजी से बढ़ती आबादी पर लगाम लगेगी और

### सुनवाई में शामिल होना है तो एनजीओ को जमा करने होंगे दो लाख रुपये

- सुपीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुतों के स्थायी पुनर्वास को लेकर दिए गए आदेश के खिलाफ व्यक्तिगत अर्जी दाखिल करने वाले को 25 हजार और गैर सरकारी संगठन को दो लाख रुपये सुपीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने होंगे।
- यह राशि सात दिन में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा उन्हें मामले में आगे पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पैसे का उपयोग आवारा कुतों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में किया जाएगा।

उनकी संख्या में कमी आएगी। हालांकि, यह केवल आदर्श स्थिति में ही संभव है। बताते चलें, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से रैबीज होने की मीडिया रिपोर्ट पर 28 जलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए सनवाई

### फैसले की पांच बड़ी बातें

- सुप्रीम कोर्ट ने पशु प्रेमियों को आवारा कुतों को गोद लेने की छूट दी है, पर उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो कुता उन्होंने गोद लिया है वह सडक पर वापस नहीं होना चाहिए।
- शीर्ष अदालत का यह आदेश देशभर में समान रूप से लागू होगा। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।
- प्रत्येक नगर निकाय एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, जिसमें इन आदेशों के उल्लंघन की शिकायत की जा सके। जैसे ही कोई शिकायत आती है, संबंधित व्यक्ति या एनजीओ पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
- अदालत ने सभी नगर निकायों को मौजूदा ढांचागत संसाधनों जैसे डाग शेल्टर की संख्या, पशु विकित्सक, कुता पकड़ने वाले लोग, कुता पकड़ने का विशेष वाहन और पिंजड़े आदि की संख्या बताने का निर्देश दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में आवारा कुतों की समस्या से संबंधित लंबित याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट स्थानांतिरत कर ली है। इन पर इस मामले के साथ ही सुनवाई होगी।

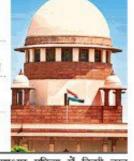
शुरू की थी। इस सिलसिले में 11 अगस्त को दिए गए फैसले के खिलाफ कुछ पशु प्रेमी और एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

रेबीज से सबसे अधिक संख्या में जान गंवाते हैं भारतीय पेज>>5

## प्रारूप सूची से बाहर हुए लोग आधार या 11 दस्तावेज में से किसी के साथ कर सकेंगे आवेदन : सुप्रीम कोर्ट

#### बिहार में एसआइआर

- यानी सिर्फ आधार कार्ड धारक भी कर सकेंगे आवेदन, आनलाइन भी किए जा सकेंगे दाखिल
- राजनीतिक दलों के एसआइआर प्रक्रिया में आगे
   आकर लोगों की मदद नहीं करने पर जताई हैरानी
- इसके बाद बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मामले में बनाया पक्षकार
- एसआइआर प्रक्रिया में नहीं किया किसी तरह का बदलाव, समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं मानी



जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सप्रीम कोर्ट ने शक्रवार को चनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में प्रारूप मतदाता सची में शामिल नहीं किए गए मतदाताओं को आधार कार्ड या मतदाता सची के विशेष गहन पनरीक्षण (एसआइआर) में निर्धारित 11 दस्तावेज में से किसी एक के साथ अपना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दे। कोर्ट ने आर्दश में 11 दस्तावेज या आधार कार्ड शब्द लिखाया है यानी जिसके पास आधार है, वह भी आवेदन कर सकता है। साथ ही कहा कि लोग आनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, फिजिकल तौर पर फार्म जमा करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने बिहार के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों हारा आगे आकर लोगों को फार्म भरने में मदद नहीं करने पर हैरानी जताई। इसके बाद राज्य के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मामले में पक्षकार बना दिया।

जिस्टस सूर्यंकांत और जिस्टस जोयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। पीठ

ने एसआइआर प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, वह निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक चलती रहेगी क्योंकि उसने एसआइआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं मानी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आगे जरूरत हुई तो देखेंगे। पिछली सुनवाई पर अदालत ने चुनाव आयोग को प्रारूप मतदाता सूची से बाहर हो गए करीब 65 लाख मतदाताओं की सूची और उनको बाहर करने का कारण वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया था।

शुक्रवार को आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। यह सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, पुच्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, पंचायत और ब्लाक स्तरीय कार्यालय, वेबसाइट और इंटरनेट मीडिया हैंडल पर उपलब्ध हैं। सूचियां हर मतदान केंद्र पर भी लगा दी गई हैं। अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल की है जिसे कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया।

एक भी पात्र मतदाता नहीं छूटेगा पेज>>4

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दल स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें प्रेज>>4

# पीएम हो या सीएम, जेल जाएंगे तो छोड़नी होगी कुर्सी : मोदी

राज्य ब्यूरो, जागरण 🏻 षटना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में मगध क्षेत्र के छह जिले एवं 30 विधानसभा क्षेत्र के राजग कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम हो या सीएम, जेल जाएंगे तो कुर्सी छोड़नी होगी। साथ ही संविधान की मर्यादा तार-तार नहीं होने देने के भरोसे को विस्तार दिया। मोदी ने कहा कि ऐसा कानून बनाने की घोषणा की जिसके दायरे में मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आएंगे। राजद एवं वामदल लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वे गस्से में हैं। उन्हें किस बात का डर हैं? राजद और कांग्रेस के कुछ नेता बेल (जमानत) पर हैं। रेल के खेल में अदालत का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ जमानत पर बाहर हैं। उन्हें इस बात का डर है कि जेल चले गए तो सारे सपने चकनाच्र हो जाएंगे। इतने बौखलाए हैं कि मुझे गाली तक दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह बातें बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहीं। मोदी ने विशिष्ट शैली के जरिये लोगों से संवाद करते हुए कहा, ऐसे लोग एक जनहित कानून का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब ने जनप्रतिनिधियों के बारे में भ्रष्टचार की कल्पना तक नहीं की होगी, लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। यह संकल्प सिद्ध होकर रहेगा।

एक मंच पर दिखा पक्ष—विपक्ष पेज>>4 टीएमसी जाएगी भाजपा आएगी पेज>>4

- तीन नए बिल संसद में पेश करने के बाद पहली बार बोले पीएम
- कहा–घुसपैटियों का बढ़ना चिंता का विषय, इन्हें बाहर करके रहेंगे
- कहा, बिहार के सीमांत जिलों में बदल रही है डेमोग्राफी
- 13 हजार करोड़ की योजनाओं
   का शिलान्यास-उद्घाटन किया



विहार के गयाजी में शुक्रवार को जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (दाएं)। प्रेट्र

### बदल रही देश की डेमोग्राफी

घुसपैठियों के कारण तेजी से बदल रही देश की डेमोग्राफी के साथ बिहार के सीमावर्ती जिलों को जोड़ते हुए मोदी ने विपक्षी दलों को सख्त संदेश दिया। कहा, घुसपैठियों को भारत का भविष्य नहीं तय करने देंगे। हर घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई होगी। इसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर महागठबंधन द्वारा की जा रही वोटर अधिकार यात्रा का जवाब माना जा रहा है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के उपरांत देश के सीमावर्ती राज्य असम एवं बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से देश में घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी में तेजी से हो रहे बदलाव को बोधगया में विस्तार देकर राजग का नया राष्ट्रीय एजेंडा भी बना दिया।

### नीतीश के कामों की प्रशंसा की

डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार के लिए किए गए निर्णय एवं कार्यों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। जनसमूह से संवाद करते हुए कहा कि यहीं पर लोगों को रोजगार मिले, वे सम्मान के साथ जी सकें, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बड़े–बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इसके पूर्व उन्होंने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। गया–दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस के अतिरिक्त वैशाली–कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मंच पर मोदी के साथ बिहार राजग के सभी शीर्ष नेता एवं केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। सिमरिया में गंगा पर बने सबसे चौड़े छह लेन पुल के लोकार्पण के उपरांत मोदी कोलकाता गए।

### नीतीश की राजनीति का पिंड दान कर गए मोदी

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक्स हैंडल पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गयाजी में मुख्यमंत्री नीतीश की राजनीति का पिंडदान कर दिया। दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राजद अध्यक्ष द्वारा नीतीश कुमार के लिए प्रयोग किए गए शब्द निंदनीय हैं।

# आनलाइन गेमिंग विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून आज हो सकता है अधिसूचित

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क: राष्ट्रपति ह्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को आनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती हैं। हालांकि इससे जुड़ा कानून प्रभावी हो, इससे पहले ही प्रमुख आनलाइन गेमिंग कंपनियों ने देश में चलाए जा रहे अपने मनी गेमिंग के 'खेल' को समेट लिया है। सरकार ने विधेयक के पारित होते ही इसे बगैर देरी के तुरंत ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था।

नए कानून में ऐसी सेवाएं देने वालों पर तीन साल तक की कैंद्र व एक करोड़ रुपये तक के जुमाने का प्रविधान है। ऐसे प्लेटफार्म का विजापन या प्रचार करने पर भी दो साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जर्माना हो सकता है। कानून बनने के बाद सरकार का फोकस रियल मनी आनलाइन गेम पर रोक लगाने की रहेगी। आइटी सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि कानन के अन्य नियमों को बनाने में अभी समय लगेगा, उससे पहले निषेधात्मक प्रक्रिया अमल में रहेगी। यह भी बताया कि बाकी प्रविधानों के लिए नियम बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही, एक नियामक प्राधिकरण बनाने पर भी काम चल रहा है, जो आनलाइन गेमिंग क्षेत्र की देखरेख करेगा।

आइटी सचिव ने कहा, कानूनी ढांचा तैयार करने की तैयारी शुरू, नियामक प्राधिकरण भी बनेगा



एस. कृष्णन।

फाइल

3,240 करोड़ का वैश्वक बाजार है आनलाइन गेमिंग का

1,800 गेमिंग स्टार्टअप चल रहे थे देश में

20 प्रतिशत उपयोगकर्ता भारत में

रियल मनी गेम है क्या: आनलाइन रियल-मनी गेमिंग उन डिजिटल प्लेटफार्म को संदर्भित करता है जहां खिलाड़ी खेलों में भाग लेने के लिए भुगतान करते हैं और नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। इनमें नकद दांव और मौद्रिक जीत वाले सभी आनलाइन गेम शामिल हैं। 15 प्रतिशत भागीदारी गेमिंग एप डाउनलोड में

15 करोड़ उपयोगकर्ता हैं जुपी एप पर 2,600 करोड़ गेमिंग से कमाए सरकार ने बीते पांच साल में

प्रतीकात्मक

12 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं एमपीएल के

60 से ज्यादा गेम संचालित करती थी एमपीएल

### कानून में ये है खास

- कानून के उल्लंघन पर तीन साल कैद या एक करोड़ रुपये जुर्माना या दोनों
- विज्ञापन करने पर दो साल जेल या 50 लाख
   जुर्माना या दोनों
- लेनदेन की सुविधा देनेवाले बैंक पर भी सख्ती
- आनलाइन गेम खेलनेवाले अपराधी नहीं पीड़ित माने जाएंगे

लीगल गेमिंग से जुड़ी कंपनियां उत्साहित

देश में पहले ही ई-स्पोर्ट्स और ई-सोशल जैसे आनलाइन गेम और नियमों के तहत संचालित होने वाली कंपनियां इस कानून के बाद काफी उत्साहित भी दिख रही है। उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें एक अच्छी ग्रोध मिलेगी। ई-गेमिंग फेडरेशन के सीईओ अनुराग सवसेना का मानना है कि एक पारदर्शी कानून आनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने मे मदद करेगा। इससे इस क्षेत्र का संतुलित और सुरक्षित विकास होगा।

45 करोड़ लोगों को गेमिंग से होता है हर साल नुकसान

20 हजार करोड़ गंवाते हैं लोग हर साल, सरकार का दावा कानूनी मान्यता मिलने और वितीय पोषण से ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को संस्थागत बढ़ावा तो मिलेगा, लेकिन विधेयक में टैक्स चोरी, अर्थव्यवस्था को नुकसान व करोड़ों युवाओं का भविष्य तबाह होने की जो चिंता जताई गई, उसे रोकने और खत्म करने के लिए पर्याप्त प्रविधान नहीं हैं। – विराग गुप्ता, साइवर कानून विशोषज्ञ।

धडाधड़ गिरने लगे गेमिंग कंपनियों के शटर: कानून प्रभावी हो, इससे पहले ही प्रमुख आनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपने मनी गेमिंग के 'खेल' को समेट लिया है। इनमें 25 करोड़ से अधिक यूजर्स वाली गेमिंग कंपनी विन्जो शामिल है। जिसने अधिकारिक बयान जारी कर 22 अगस्त से इसके दायरे में आने वाले

अपनी सेवाओं को वापस लेने का पैलान किया है।

इसके साथ ही ड्रीम-11, रमी सर्किस जैसी प्रमुख आनलाइन गेमिंग कंपनियों ने भी नए कानून के दायरे में आ रहे वाले अपने गेम्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं। आनलाइन गेमिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी व यूजर्स की संख्या को देखते हुए गेमिंग कंपनियों ने जल्द ही नए कानून के दायरे में रखकर नई शुरूआत करने के संकेत दिए है। जिसमें मनी गेमिंग के लिए कोई जगह नहीं होगी। नए कानून के तहत आनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म पर ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को नए स्वरूप में लाने पर काम शुरू कर दिया गया है। इनमें भारतीय पारंपरिक खेलों व मनोरंजन से जुड़े खेलों को जगह दी जा सकती है।

नजारा टेक के शेवरों में 17 प्रतिशत की गिराबट: आनलाइन गेमिंग पर रोक से जुड़े कानून के आने के बाद आनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेवरों में भी भारी गिराबट देखी जा रही है। पोकरबाजी गेम संचालित करनेवाली मनशाइन टेक्नोलाजी

की सहयोगी नजारा टेक्नोलाजी के शेयरों में तीन कारोबारी दिनों में 17.52 प्रतिशत की गिराक्ट दर्ज की गई है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 4.98 प्रतिशत की गिराक्ट के साथ 1155.75 पर बंद हुए। वहीं डेल्टा कार्प के शेयर 3.50 प्रतिशत, जबकि आनमोबाइल ग्लोबल का शेयर 2.73 प्रतिशत गिराक्ट के साथ बंद हुए।

# तियानजिन में होगा एससीओ के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन : चीन

### पीएम मोदी समेत 20 वैश्विक नेता होंगे शामिल

बीजिंग, प्रेट्र: चीन ने शुक्रवार को कहा कि तियानजिन में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन इस संगठन के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित वैश्विक नेता शामिल होंगे। यह सम्मेलन 31 अगस्त से एक सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। चीन पांचवीं बार इस 10 सदस्यीय समूह की मेजबानी करने वाला है।

चीन के सहायक विदेश मंत्री लिय बिन ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, इस सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमख नेताओं में चीन के राष्ट्रपति शी चिनिर्फंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, तुर्किये के राष्ट्रपति रीसेप तैयप एर्दोगन शामिल हैं। सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनामी प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्भद मुइज्जु भी शिरकत करेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस व एससीओ के महासचिव नुर्लान येरमेकेबायेव समेत 10 अंतरराष्ट्रीय

31 अगस्त- एक सितंबर को होने वाला है यह सम्मेलन



शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)।

फाइल

संगठनों के अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। लियु ने कहा कि चिनिर्फंग एससीओ प्रमखों की 25वीं परिषद की बैठक और एससीओ प्लस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चीन इस वर्ष एससीओ का अध्यक्ष है। एससीओ में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान. पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और चीन शामिल हैं। एससीओ प्लस शिखर सम्मेलन को बीजिंग द्वारा बढ़ती वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीद है कि सम्मेलन में शामिल हो रहे अधिकतर नेता इस सम्मेलन के बाद भी तीन सितंबर को बीजिंग में होने वाली चीन की सैन्य परेड को देख सकते हैं।

## अगले हफ्ते जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले हफ्ते जापान व चीन की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी पहले 29-30 अगस्त, 2025 को जापान जाएंगे और इसके बाद 31 अगस्त से एक सितंबर, 2025 तक चीन जाएंगे। चीन में पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे और साथ ही वहां कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे।

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएम शिगेरू इशीबा के आमंत्रण पर पीएम मोदी जापान जाएंगे, जो उनकी आठवीं जापान यात्रा होगी। पीएम मोदी और पीएम इशीबा की अगुवाई में भारत-जापान सालाना बैठक का आयोजन होगा। यह पीएम इशीबा के साथ पीएम मोदी की पहली सालाना बैठक होगी।

जापान व भारत की सालाना बैठक में रक्षा व सुरक्षा, कारोबार व इकोनमी, प्रौद्योगिकी व अन्वेषण सहयोग पर बात होगी और साथ ही क्षेत्रीय व वैश्विक हालात पर भी चर्चा होगी। जानकारों ने प्रधानमंत्री मोदी की सात वर्षों बाद चीन यात्रा होगी, भारत-जापान सालाना बैठक में शामिल होंगे



पीएम नरेन्द्र मोदी।

INIZA

बताया है कि जापान की तरफ से इस बैठक में भारत में नये निवेश की घोषणा की जाएगी। जापान के बाद राष्ट्रपति शी चिनिकंग के आमंत्रण पर पीएम मोदी चीन जाएंगे। यह पीएम मोदी की सात वर्षों बाद चीन यात्रा होगी। दो दिन पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि वह चीन यात्रा को लेकर उत्सुक हैं। चीन के राजदूत शु फीहोंग ने एक दिन पहले कहा है कि चीन व भारत के अधिकारी मोदी की यात्रा को सफल बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं।

# अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में हमने खींच रखी है लक्ष्मण रेखा: जयशंकर

सख्त रुख > विदेश मंत्री ने कहा, हम अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता खत्म नहीं हुई है। यह जारी है। लेकिन, भारत ने किसानों व छोटे कारोबारियों को देखते हुए अपनी तरफ से रेड-लाइन (लक्ष्मण रेखा) खींच रखी है। हम अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। पिछले एक सप्ताह के दौरान अमेरिका के वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा भारत पर लगाए गए एक-एक आरोप का जयशंकर ने जवाब दिया है। उन्होंने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा कि भारत अपनी नीतियों में किसी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा और पाकिस्तान के साथ संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। रूस से तेल खरीद कर मुनाफा कमाने के टंप प्रशासन के आरोपों पर जयशंकर ने दो टूक कहा कि यह बहुत ही हास्यास्पद है कि जो लोग अमेरिकी प्रशासन के कारोबारी हितों के लिए काम कर रहे हैं. वे हम पर कारोबार करने का आरोप लगा

अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए हालिया टैरिफ को अनुचित और असंगत करार दिया

कहा, रूस से तेल आयात के मुद्दे पर भारत को निशाना बनाया जा रहा है

चीन और कुछ यूरोपीय देश बड़े आयातक होने के बावजूद आलोचना से बचे हुए हैं



एस जयशंकर। फाइल

### चीन से संबंध सुधरने के पीछे अमेरिका से तनाव नहीं

विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि नई दिल्ली – वाशिंगटन संबंधों में तनाव के मद्देनजर चीन के साथ भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हर चीज को एक साथ जोड़कर किसी खास स्थिति के लिए एकीकृत परिस्थिति का जिक्र करना एक गलत विश्लेषण होगा। बताते चलें, ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ थोप देने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के संबंधों में खटास आ गई है। दूसरी तरफ, भारत और चीन के संबंधों में पिछले कुछ समय से सुधार हो रहा है।

रहे हैं।

शनिवार को एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में जयशंकर ने राष्ट्रपित ट्रंप के उस दावे को खारिज किया, जिसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य तनाव को कम करने में भूमिका निभाने की बात कही थी। विदेश मंत्री ने कहा, लगभग 50 वर्षों से भारत की नीति रही है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी संप्रभुता

### अमेरिका न भूले, कहां छिपा था ओसामा बिन लादेन

पाकिस्तान और अमेरिका के 'ऐतिहासिक संबंधों' पर खास तौर पर टिप्पणी करते हुए जयशंकर ने कहा कि उनका एक-दूसरे के साथ का इतिहास रहा है। हालांकि, उनके पास अपने इतिहास को नजरअंदाज करने का भी इतिहास रहा है। यह वही सेना है, जो एबटाबाद गई थी और वहां किसे पाया था? वह वर्ष 2011 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने के अमेरिकी सेना के आपरेशन की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने राजनीतिक फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया है।

और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर दृढ़ है और बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा।

अमेरिका से जारी है कारोबारी समझौते की वार्ता पेज>>11

# चीन पर निर्भरता को खत्म करने की जरूरत

विशेषज्ञों ने कहा, बीजिंग का रेयर अर्थ मैग्नेट और खाद की सप्लाई शुरू करना चालाकी भरा कदम

राजीव कुमार 🏻 जागरण

नई दिल्ली : भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री की तरफ से रेयर अर्थ मैग्नेट और खाद की सप्लाई शुरू करने का भरोसा दिया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे भारत को खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट और खाद की तरह भारत अब भी विभिन्न महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। इनकी सप्लाई बाधित होने पर हमारा निर्यात और घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग प्रभावित हो सकती है। भारत के प्रति चीन के पूर्व रवैये को देखते हुए चीन कभी भी ऐसा कर सकता है।

पिछले स्माल भारत ने चीन से लैपटाप के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उससे पहले तक करीब 90 प्रतिशत लैपटाप चीन से आ रहे थे। अब भी लैपटाप व इलेक्ट्रानिक्स आइटम के निर्माण से जुड़े कच्चे माल का भारी  एरिश्रोमाइसिन से लेकर लैपटाप तक के लिए होना होगा आत्मिनर्भर

 आयात में 50% तक की कटौती का लक्ष्य तय करके काम करें 100 अरब डालर रहा व्यापार घाटा पिछले वित वर्ष 2024-25 में भारत और चीन के बीच





चीन ने भारत को जो थोड़ी छूट दी है, वह चीन का चालाकी भरा कदम है। भारत को अगले पांच साल में चीन से होने वाले आयात में 50 प्रतिशत तक की कटौती का लक्ष्य तय करके काम करना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रानिक्स वस्तु से लेकर उपभोक्ता वस्तु और इलेक्ट्रिक वाहन

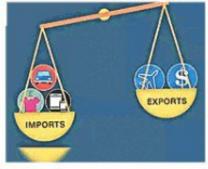
में इस्तेमाल होने वाले लिथियम से लेकर कई रोजमर्रा की चीजें चीन से आ रही है।

-अजय श्रीवास्तव, संस्थापक, जीटीआरआइ

मात्रा में चीन से आयात किया जाता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंशिएटिव (जीटीआरआइ) के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष तक एंटीबायोटिक दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 97 एरिश्रोमाइसिन के लिए भारत चीन पर निर्भर था। इलेक्ट्रानिक और चिप निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 96 प्रतिशत सिलिकन वेफर, 82 प्रतिशत सोलर सेल तो 98 प्रतिशत विस्कास यार्न के लिए भारत की चीन पर निर्भरता है।

### व्यापार घाटे में हुई 17 प्रतिशत की वृद्धि

चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह 100 अरब डालर ह गया। इस अवधि में भारत ने चीन को सिर्फ २७.७ अरब डालर का निर्यात किया और चीन से 100 अरब डालर का आयात किया। इस व्यापार घाटे में पूर्व के वित्त वर्ष के मुकाबले 17 प्रतिशत की बढोतरी रही। चालु वित्त वर्ष 2025-26 में भी अप्रैल-जुलाई में सबसे अधिक चीन से 40.66 अरब डालर का आयात किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष की सम्प्रन अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। हालांकि इस साल अप्रैल- जुलाई में चीन होने वाले निर्यात में इजाफा हुआ है। निर्यात सिर्फ 5.76 अरब डालर का है। चीन से व्यापार कहने वाले व्यापारियों



के मुताबिक कुछ सालों से चीन के इंजीनियर को भारत में वीजा मिलने में होने वाली दिवकत को देखते हुए मशीन बेचने वाली चीन की कंपनियां भारत के इंजीनियर को अपनी टेक्नोलाजी सिखाने के लिए तत्पर दिख रही थी। अब चीन के इंजीनियर आसानी से अगर भारत आ जाएंगे तो वे भारतीय इंजीनियर को टेक्नोलाजी क्यों सिखाएंगे।

चीन ने हाल ही में भारत स्थित एपल स्मार्टफोन की फैक्ट्री से अपने इंजीनियर को वापस बुला लिया था।

## Centre is denying fair share of funds, acting politically, says Stalin

#### The Hindu Bureau CHENNAI

Though Tamil Nadu contributes significantly to Union tax revenue through direct taxes and the Goods and Services Tax (GST), the Centre does not give the State its due share when it comes to financial devolution, acting with "narrow political motives", Chief Minister M.K. Stalin said on Saturday, accusing the Centre of undermining the independence of the Finance Commissions.

Addressing a national seminar on Union-State relations, Mr. Stalin urged other States to join the fight to protect their rights. "All those who truly care national unity should lend their voices to the cause of State autonomy. Like Tamil Nadu, other States should also constitute similar committees to take forward the demand for rights and federalism," he said.

"In 2007, at the insistence of the DMK, the UPA government constituted the Punchhi Commission. One of its key recommendations was that Governors should be appointed in consultation with the respective Chief Ministers, in a non-partisan manner. Yet this was never implemented, as is evident from the actions of the present Tamil Nadu Governor," he said.

The Union government continues to trouble Opposition-ruled States through legislative and administrative interference, Mr. Stalin said. Recounting the histo-



M.K. Stalin

ry of the battle for State autonomy in the federal system, he recalled former Chief Minister C.N. Annadurai's demand in 1967 for a review of the Constitution to secure States' rights and former Chief Minister M. Karunanidhi's initiative in setting up the Justice Rajamannar Committee in 1969 to examine Union-State relations.

Even though the Sarkaria Commission, formed in 1983, highlighted the dangers of excessive centralisation, Mr. Stalin said that it had failed to recommend meaningful constitutional amendments to empower the States. "Since then, successive amendments and legislations have only vested more powers with the Union," he noted.

#### Language policy

He said that the Union government is pushing Hindi, and Tamil Nadu has successfully resisted such attempts. Today, resistance to Hindi imposition and demands for State rights are being echoed by other States he said, emphasising that it is only through the strength of self-reliant States that a united India can grow stronger.

## What's the issue with the map of Africa?

Why does the African Union want the Mercator map replaced? Is the continent depicted as smaller than it is? How did this come about? Has this affected the perception about Africa? What are the alternatives to correct the distortions? What lies ahead?

Vasudevan Mukunth

#### The story so far:

he African Union (AU) has endorsed the 'Correct the Map' campaign to replace the Mercator map projection with alternatives such as the Equal Earth map. At the heart of this demand is the charge that the Mercator projection, still widely used in schools, media, and online platforms, systematically distorts the sizes of landmasses, shrinking Africa while inflating Europe, North America, and Greenland. By backing the call, the AU has expressed hope that a fairer projection will restore geographical accuracy and correct what it characterises as centuries of symbolic marginalisation.

#### Why is the Mercator map under fire?

The Mercator projection was designed in 1569 by Flemish cartographer Gerardus Mercator, who was trying to solve a navigation problem. On a globe, a ship sailing in a constant compass direction, called the rhumb line, curves when drawn on most map types. This made it awkward for sailors to translate a bearing into a usable course they could plot on a chart.

Mercator's projection stretched the north-south scale so that all rhumb lines appeared as straight lines. Sailors could now draw a straight line across the map at a chosen compass angle and follow that heading consistently at sea. Thus, together with Edward Wright's 1599 mathematical tables, the Mercator projection is believed to have catalysed European exploration and colonial expansion. To achieve this convenience, Mercator distorted scale: landmasses close to the poles appeared larger while those near the equator appeared smaller than in reality.

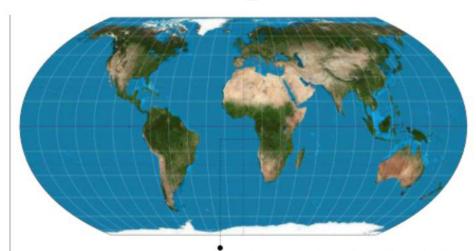
As a result, Africa, which covers 30 million sq. km, often appears on Mercator maps roughly as large as Greenland, which is 14x smaller. Europe also looks comparable in size to Africa although the continent is a third as large. Similarly, Canada, Russia, and northern Europe appear bloated while tropical regions like Africa, South America, and India are diminished.

Over time, wall maps in offices, atlases, and on digital platforms defaulted to Mercator's rectangular format because it was familiar and convenient. It was further reinforced by textbooks of the 20th century.

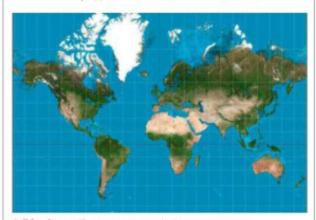
However, critics have argued that such distortions subtly condition how people perceive relative importance. A continent depicted as smaller seems less powerful and even less worthy of attention.

#### Why are maps distorted?

There is no perfect way to flatten the surface of a sphere onto a rectangle, rendering every map a compromise. Mathematicians and cartographers tasked with projecting a globe onto a plane need to distort one or more of area, shape, distance or direction. Experts have said the choice of which property to preserve and which to



Different perspective: The Equal Earth projection preserves the relative sizes of continents and countries, ensuring Africa appears far larger than Europe or Greenland, as it is in reality. However, landmasses also appear curved or stretched. STREBE (CC BY-SA)



Call for change: The Mercator map projection. STREBE (CC BV-SA)

surrender is a technical as well as political act.

The Mercator projection is a conformal map, which means it preserves local shapes and angles. But to achieve this, Mercator stretched landmasses near the poles, inflating their apparent size and diminishing those of equatorial regions like Africa and South America. In contrast, the Equal Earth projection preserves the relative sizes of continents and countries, ensuring that Africa appears far larger than Europe or Greenland, as it is in reality. However, landmasses also appear curved or stretched. The orthographic projection makes a different trade-off. It portrays the earth as it would look from space, as if viewed from a great distance. While this choice makes it visually intuitive, this projection is limited by the fact that it shows only one hemisphere at a time and areas near the edges appear compressed.

#### How does the distortion affect Africa?

Experts have said for many years now that the Mercator projection has reinforced Africa's marginalisation in the global imagination. By making the continent look small, the map suggested, consciously or not, that Africa was less consequential. This perception seeped into textbooks, policymaking, and popular culture.

As Rabah Arezki, a former World Bank economist, has said, the "standard projection was a political tool" that aided colonial domination, making Africa look "small and conquerable then" and "irrelevant now". Likewise, the AU's deputy chairperson Selma Malika Haddadi has described the Mercator map as falsely portraying Africa as "marginal".

Thus, the AU as well as advocacy groups like Africa No Filter and Speak Up Africa have articulated a move away from the Mercator projection as a way to reclaim dignity.

#### What happens next?

The leading alternative to the Mercator projection is the Equal Earth projection, created in 2018 by Tom Patterson (U.S. National Park Service), Bojan Šavrič (then with American GIS company Esri), and Bernhard Jenny (Monash University, Australia). It preserves relative areas sacrificing shape, that is, continents appear stretched or curved.

Another option is the Gall-Peters projection repopularised in the 1970s. It also preserves area but stretches continents vertically, making them appear elongated. Just as Mercator wanted to help sailors, as political scientist Arthur Klinghoffer wrote in his 2006 book, *The Power of Projections*, "Peters was trying to challenge basic assumptions inherent in the Mercator projection with the aim of influencing social and political attitudes. His elongated images were shocking, and made people examine their cartographical frame of reference."

In 1979, a 21-year-old Australian named Stuart McArthur published the "Universal Corrective Map of the World" that turned the world map 180° and showed Australia at the top. He was reportedly sick of being teased as being from "Down Under".

The AU's endorsement is the most significant institutional backing yet for the 'Correct the Map' campaign. Campaigners have also petitioned the UN Committee of Experts on Global Geospatial Information Management to adopt Equal Earth. The World Bank has already said it is phasing out the Mercator map in favour of Equal Earth. National Geographic and NASA's Goddard Institute for Space Studies have also been using it. Google Maps introduced a 3D globe option in 2018, although its mobile app still defaults to Mercator.

This isn't expected to be easy, however, as the Mercator projection is entrenched in classrooms, news graphics, and even some AU-affiliated websites. Displacing it altogether will entail revising textbooks, redesigning curricula, updating digital interfaces, and overcoming institutional inertia.

'The Mercator map falsely portrays Africa as marginal'

# Help EC bring back deleted voters: SC to parties

Court says voters can file objections online; they can use Aadhaar or any other valid documents

Bench directs parties and their booth-level agents to assist excluded voters in the process It says party workers are best placed to help people, questions the distance between parties and voters

Krishnadas Rajagopal NEW DELHI

he Supreme Court on Friday directed political parties contesting the Bihar Assembly election to help the Election Commission (EC) bring back voters left out of the draft electoral roll published as part of the ongoing special intensive revision (SIR) exercise.

A Bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi directed State party chiefs to instruct their booth-level agents to assist excluded voters file their claims and objections for inclusion in the rolls.

The court order conveyed a sense of urgency, with barely over a week left before the claims-and-objections stage of the SIR ends on September 1.

The court clarified that voters can file their claims and objections online in a bid to save time. Excluded voters can either attach their Aadhaar card, as permitted by the SC, or any of the 11 indicative documents listed by the EC, as proof of identity and residence, with their claims.

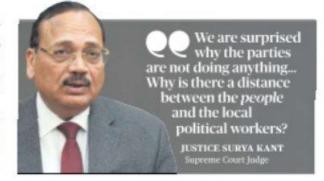
Senior advocate Kapil Sibal, representing the RJD, urged the court to extend the deadline beyond September 1.

Justice Kant asked the EC to "examine" this aspect if there was an "overwhelming response" from excluded voters.

Justice Bagchi remarked that with the inclusion of Aadhaar as a relevant document in the claims-and-objections stage, the EC may need more time to complete the verification of the pleas filed for inclusion in the electoral roll.

#### 'Why a distance'

At one point, the court seemed to blame the political parties for not taking the *initiative* to assist the



voters, and for bringing things to such a pass at the eleventh hour.

"We are surprised why the parties are not doing anything. Political workers are the best persons in rural areas and villages. Why is there a distance between the people and the local political workers?" Justice Kant asked.

The EC, represented by senior advocate Rakesh Dwivedi, criticised political parties for taking a contrarian view about the SIR. He assured the court that no eligible voter would be left out of the electoral process.

"Political parties have 1.6 lakh BLAs. Each BLA can verify 10 excluded names on the list. That would be 16 lakh names a day. It will take only five days for BLAs to verify the list. This is in addition to individual excluded voters also coming forward to file claims," Mr. Dwivedi said, conveying the EC's optimism in court.

He said that 84,305 claims have been initiated so far. Over 2.5 lakh new voters who have recently reached the age of 18 in Bihar have come forward to join the electors' ranks, signalling the groundswell to join the electoral process.

"Political parties merely raise hue and cry to serve their political ends... Political parties could appoint more BLAs, but they will not," Mr. Dwivedi said, expressing the poll body's disappointment with the conduct of the parties.

#### 'Parties can assist EC'

The Bench said that claims and objections may not come from all the 65 lakh excluded voters. It quoted the EC's figures that 22 lakh among the 65 lakh were dead, while 36 lakh had migrated out of Bihar, and eight lakh were duplicate entries on the roll. "So, it is just that names from the migrated 36 lakh have to forward come claims," Justice Kant summarised.

"Political parties could

play a role in assisting the EC. They could verify the names. The Chief Election Commissioner had held a press conference inviting political parties, mass organisations, etc, to assist the EC," Mr. Dwivedi appealed.

The court impleaded the parties as respondents, issued notice and directed status reports to be filed on September 8, the next date of hearing.

Senior advocate Gopal Sankaranarayanan, intervening on behalf of voters' groups from Bihar, objected to the emphasis on "minutiae" when the very legality of the SIR process was under dispute in the top court.

"All this minutiae is being presented as if the entire SIR is legal. There is no legal basis for filing enumeration forms. One day they will come in Delhi with pre-filled enumeration forms," Mr. Sankaranarayanan objected.

Justice Kant replied that larger questions would be looked into later on.

#### 'Voter-friendly'

Mr. Sibal and senior advocate A.M. Singhvi, appearing for several other Opposition parties, including the Congress, said the present litigation was "not about BLAs, but the rights of the ordinary voters of Bihar".

Justice Kant made a brief comment that "the entire exercise should be voter-friendly".

Advocates Prashant Bhushan and Neha Rathi, for the Association for Democratic Reforms, countered the EC's submission that only two claims and objections had been received through the BLAs so far.

"BLAs are not being permitted to submit objections," Mr. Bhushan submitted.

# Forest rights of tribals not settled for Great Nicobar project: council

Tribal representatives' body complains to Minister; says Andaman and Nicobar administration gave a 'false' report to Centre stating that tribespeople's rights under FRA were settled with regard to diversion of forest land for the ₹72,000-cr. project

#### Abhinay Lakshman

NEW DELHI

¬ he Andaman and Nicobar Islands administration made a false representation to the Centre claiming that rights of the tribal people under the Forest Rights Act, 2006, had been "identified and settled", which eventually led to forest clearances being granted for the ₹72,000-crore mega infrastructure project on the Great Nicobar Islands, a council representing the Nicobarese has said in a complaint to Union Minister of Tribal Affairs Jual Oram.

The proposed Great Nicobar Island Project will include a transshipment port, an airport, a power plant, and a township.

Local tribespeople had raised several concerns, including the diversion of nearly 13,075 hectares of forest land for the project and its impact on vulnerable groups in the area.

Soon after taking charge



The proposed project on the islands will include a transshipment port, an airport, a power plant, and a township. ISTOCKPHOTO

in 2024, Mr. Oram told *The* Hindu that his Ministry would look into the issues raised by them.

Earlier this year, he said their concerns are "being examined", without going into the details.

#### Certificate issued

"In the last two months, we have found that the administration in A&NI issued a certificate in 2022 saying the FRA rights were identified and settled, and that the consent for diversion of forest land was taken only after this," a member of the Tribal Council of Little Nicobar

and Great Nicobar told The Hindu on Friday.

The council is the key representative body of the Nicobarese on the islands, and has been interacting with the administration on various issues.

The council, in a letter to Mr. Oram dated July 21, clarified that it had not given its consent for the project. "We write to you to inform that the process of settlement of forest rights under the FRA has not even been initiated. Therefore, there is no question of forest rights being settled." The council said it had recently been made aware of an August 2022 "certificate", issued by the Deputy Commissioner of Nicobar District that claimed the opposite.

According to this forest diversion certificate under the FRA issued on August 18, 2022, a copy of which was seen by The Hindu, the administration said: "The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire protected forest area of 121.87 sq. km. and deemed forest of 8.8 sq. km. falling under the project."

However, as reported by The Hindu earlier, the Union Territory administration has told the Ministry in its monthly reports that it need not implement the FRA on the islands as the forests there are already protected under the Protection of Aboriginal Tribes Act of 1956 (PAT56).

While the PAT56 gives the administrator of the islands full authority to divert forest land, the FRA allows such diversion only after rights are first settled and then consent is taken from the Gram Sabhas concerned. It was not clear if the diversion of forest land for the project was made under the FRA or PAT56.

The Centre has maintained that due process was followed for getting clearances. A Gram Sabha meeting held on August 12, 2022, had consented to the diversion of forest land, it said. However, the council says the Nicobarese of Great Nicobar were not part of the meeting.

#### 'Exploring options'

A council member who spoke to The Hindu on condition of anonymity said, "We are waiting for the Minister to reply. If it does not come, we will see what other options are available to us." The member said the council's complaint was marked delivered by the post office on July 30, adding that it had also sent an email to Mr. Oram's office but was yet to get a response.



## A dog's life in the city

Animal Birth Control, microchipping, and feeding programmes form part of the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike's plan to strengthen the co-existence of humans and canines in the city. But activists are not on board with all of these plans, writes Chetan B.C.

will not only

strengthen

programme but also

offer wider

benefits

VIKAS SULARKAR KISHOR, Special

the ABC

n August II, a Supreme Court Bench directed Delhi's local authorities to remove stray dogs from the streets of the national capital, a move that sparked nationwide debates over the right ap-proach to deal with these animals.

The ruling came even as discussions on "dog menace" had gripped Bengaluru following incidents of dog bites. A 68-year-old man, Seethappa, was mauled to death by a pack of stray dogs in northern Bengaluru's Kodigehalli. Days later, two girls were bitten by stray dogs inside Dr. B.R. Ambedkar School of Economics University on the Jnanabharathi campus of Bangalore Universi-

ty in West Bengaluru.

Following the fatality, the Karnataka Lokayukta had also pulled up Bengaluru's civic body. However, the directive was centered on curbing aggression in stray dogs by confining and monitoring them for a few days in well-main-tained kennels before releasing them.

#### Bengaluru and dog bites

Delhi recorded 25,210 dog-bite cases in 2024, Denn recorated 25,210 dogonie cases in 2021, 17,874 in 2023, and 6,691 in 2022. Although small-er than Delhi, Bengaluru recorded 13,831 dog bite cases in the first half of this year, according to Bruhat Bengaluru Maha-nagara Palike (BBMP) data.

nagara Palike (BBMP) data.
Of these, 3,472 cases involved pet dogs. Last year, the city logged 26,532 cases, including 8,000 from pet dogs (see graphics for previous years).

Officials say that the numbers may appear alarming, but context reveals otherwise. Before the

pandemic, in 2019-2020, the city reported 42,818 cases. A stronger Animal Birth Control (ABC) programme introduced after 2019 reduced the cases to 22,945 in 2022-2023.

"The rise in 2024-25 is largely because of

streamlined reporting. Since dog bites are now notifiable, cases are recorded more diligently than before," explained a senior BBMP Animal

Husbandry officer.

Reports of a spike, presented without analysis, alarmed the public. Coupled with that, the Suanarmed the public. Coupled with that, the Su-preme Court's judgement echoed in the Karnata-ka Legislative Council, where some members urged the State government to seek a similar di-rective. However, Chief Minister Siddaramaiah batted for a more "humane approach."

#### BBMP's approach a model?

The BBMP's comprehensive plan to address the issue involves ABC, microchipping, and feeding programmes. Activists and veterinarians believe this could serve as a "model" for other States. Even before the Chief Minister's reassurance,

Even before the Chief Minister's reassurance, the BBMP Animal Husbandry Department, head-ed by Special Commissioner Vikas Sularkar Kish-or, had chalked out a detailed plan earmarking 660 crore exclusively for stray dog management in 2025-26, according to data accessed by The

#### Animal Birth Control

In Delhi's case, the Supreme Court pinned the blame on local authorities for failing to run ro-bust ABC programmes, which involve capturing dogs, sterilising them, and releasing them in the exact location from where they were picked up. Hemant Kumar Agrawal, a paediatrician and aximal interpretable properties of the circle.

animal rights activist, emphasised the signifi-cance of sterilisation, not just in controlling breeding, but also in reducing hormonal changes that can trigger aggression in dogs.

The importance of sterilisation was reflected

in the BBMP's 2023 dog census. The survey estimated Bengaluru's stray dog population at 2.79 lakh, a 9% drop from 2019 when the count was

We have an 3.1 lakh Chandraiah, Joint Director, BBMP (Animal Husbandry), attributed the decline to the ABC action plan, including programme gaining momentum from 2019 veterinary Between 2020-21 and 2023-24, an average of hospitals in 50,478 dogs were sterilised and 88,666 received anti-rabies vaccination annually. In 2024-25, ste rilisation fell to 35,891, though vaccination num all eight zones. This

bers held steady at 88,572. bers held steady at 88,572.
The slump in sterilisation had two main reasons. First, the BBMP suspended the licence of an NGO involved in sterilisation after a botched surgery, which led to the closure of three ABC centres in Yelahanka, Mahadevapura, and R.R. Nagar, Second, infrastructure shortcomings cou-

pled with stricter Standard Operating Proce-dures (SOPs) laid down by the Animal Wel-fare Board of India (AWBI) slowed

Infrastructure issues

The SOPs require dogs undergoing sterilisation to be monitored for at least four days post surgery. With Bengaluru's current capacity limited to 550 dogs, the BBMP can manage only that many surgeries every four days. Additionally, a shortage of veterinarians and the difficulty of catching dogs have restricted sterilisation to 150 to 200 surgeries daily.

At present, the city has only six ABC centres and five companies with 23 teams carrying out surgeries. Bengaluru's current capacity limit

#### Five-in-one vaccination

In addition to Animal Birth Control and Rabies Vaccination (ABCRV), the BBMP has also pio-neered the use of DHPPiL, a five-in-one vaccine protecting dogs against distemper, hepatitis, parvovirus, parainfluenza, and leptospirosis, in ad-dition to rabies.

The civic body also follows a "ring vaccina tion" strategy. When a rabies case is confirmed, all dogs in contact with the infected animal are vaccinated. In Bengaluru, 114 rabies-positive cas-

vaccinated. In Bengauru, 14 Faoise-positive cases were reported in just six months, 13 less than last year, according to data.

"An increased awareness of our helpline has led to more reporting, which is a positive sign," said Chandraiah. He said it helps their larger cause of effective detection of positive cases to curb further spread of the disease. It is to be not-ed that rabies can spread across species. Vikas told *The Hindu* that the BBMP is working

to expand infrastructure and manpower. "We have an action plan, including establishing veterinary hospitals in all eight zones. This will not only strengthen the ABC programme but also off-er wider benefits," he said.

The BBMP is mulling over requesting veterin-

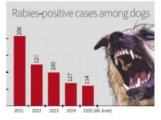
ary colleges to involve graduates in ABC opera-tions, possibly linking their degrees to perform-ing a set number of surgeries. "This would boost manpower and vaccination coverage," he

The BBMP is also considering reintroducing the Capture-Neuter-Vaccinate-Release (CNVR) technique, where dogs are captured, treated, and released within 24 hours.

#### Activists oppose move

However, activists have opposed the move, warning it risks the lives of dogs that develop post-surgery complications.
Despite these challenges, the BBMP reported progress, completing 11,700 surgeries and vacci-

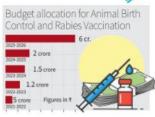
Dog-bite cases

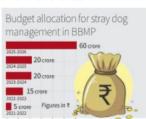


Vaccination and Animal Birth



GRAPHIC: SEBASTIAN FRANCIS





nating 71,434 dogs in just four months (April-July) this year. To ease vaccination efforts, feeders were roped in to help catch dogs, a move that worked well. The BBMP hopes to cover 2 lakh

worked well. The BBMF Hopes to cover 2 lash dogs this year. Yet, concerns remain. Activist Arun Prasad ar-gued that AWBI rules are often flouted, especially the requirement to release dogs at the same locathe requirement to release dogs at the same solt tion where they are picked up from. Relocation, he warned, often triggers aggression as unfami-liar environments cause fear. Vikas admitted some unintentional reloca-tions occurred, but insisted it was not deliberate.

sion of relocation," he explained.

Arun also stressed the need for wider vaccina
tion, pointing out that more than a lakh dogs mis
out on annual anti-rabies vaccination (ARV)
While an average of 88,666 dogs are vaccinate
annually, Bengaluru has 2.7 lakh strays, meaning
thousands go unprotected while others are re
vaccinated unnecessarily.

To fix this, the BBMP has allocated funds for
trap cages, enabling feeders to help catch dog
during sterification and vaccination drives. Mi

during sterilisation and vaccination drives. Mi crochipping is also planned to prevent duplicate vaccinations and track a dog's location.

Microchipping Currently, the BBMP relies on photographs to identify vaccinated dogs, a flawed system with no proper records. Microchipping will store details of vaccination history and location, helping to prevent relocation errors, explain BBMP officials

The civic body is preparing tenders worth ₹3.23 crore for the project.

Arun, however, warned of possible health risks for dogs. He claims that the microchip may move in the dog's body, possibly leading to unfo reseen diseases.

Officials defended the plan, noting that pilo tests showed no side effects. "The chip is just 5-4 tests showed no sade effects. The crip is just 5-t mm, injected under the skin near the neck. I stores data such as vaccination details and loca tion," a BBMP officer explained, adding that only five companies in India are eligible to execute the

While Shimla experimented with col lared QR codes, the BBMP officials dis missed the idea, saying dogs quickly re move collars, often with the help o other dogs, rendering the investm

#### Feeding programme

To address aggression caused by hunger, the BBMP has launched a

hunger, the BBMP has launched a feeding programme. Hemant Kumar explained that ma ny bites occur when dogs feel threa tened or are hungry. With garbage dumps shrinking owing to better waste collection, food scarcity has triggered more aggression. Vikas said the ₹2.88-crore project will leed 4,000 dogs in areas with frequent bite inci

dents. As of August 18, two contractors have come forward to participate in the tender. Criticism arose over the inclusion of chicker rice in the meals, but the BBMP clarified it was cooked and provided for protein. Rashmi D'Souza, former Karnataka Anima

Welfare Board member, explained that only raw flesh poses a danger by triggering wild instincts in dogs. However, the BBMP is providing cookec chicken, which she noted could be a benefit for

We urgently need to curb meat shops feeding we urgently need to curb meat snops recently stray dogs because raw flesh can evoke wild in stincts in dogs. The BBMP should issue sterr warnings to such shops about this and cautior them of revoking licences; "she said. The BBMP also plans to launch an "Each One

The BBMP also pians to latinci an "Each one Feed One" campaign to promote citizen partici pation in feeding dogs ethically. Hemant Kumar stressed that public awarenes is vital, as cruel acts by humans often provoki fear-driven bites from dogs. To this end, the BBMP is considering awareness campaigns across schools, buses, metro announcements

and bus shelters.

By rolling out multiple projects, the BBMP is attempting to address the root causes of the dog menace which are hunger, improper ABC imple mentation, and vaccination.

Activists believe that the plan is comprehen sive, except for the microchipping programme and could serve as a possible model plan for oth er States if implemented effectively. Yet, they

er states it implemented effectively, ret, treey warn that plans must not remain on paper. "Given the BBMP's reputation, many assume funds will be misused. Implementation is key to building true co-existence and reigniting hope among people," said Hemant Kumar.

among people, said remain kumar.

In sharp contrast, the Supreme Court, in it
August II directive, stated, "We are conscious and
sensitive of co-existence. The idea behind co-ex
istence is not the existence of one's life at the cos
of the other."





# Should SC sit idly as Governors block Bills: CJI

Solicitor-General says the top court has encroached into the terrain of law-making Is the court supposed to suspend its role and watch as the people's will is thwarted, asks CJI

The CJI refers to how the T.N. Governor had kept Bills pending for almost four years

Krishnadas Rajagopal NEW DELHI

hief Justice of India
B.R. Gavai on
Thursday asked the
Union government if the
Supreme Court is supposed to suspend its role as
the "custodian of the Constitution" and sit powerless
while Governors make
competent State legislatures defunct and thwart
the democratic will of the
people by sitting on Bills
for years together.

The Chief Justice, heading a Presidential Reference Bench of five judges, referred to how the Tamil Nadu Governor had kept crucial State Bills pending for almost four years without a word explaining why.

The oral observations from the Chief Justice came in response to Solicitor General Tushar Mehta's submissions for the Union government that the top court, through its April 8 judgment, had encroached into the terrain of law-making and slighted high Constitutional authorities like the Governors and the Pre-

sident by imposing time limits on them.

Mr. Mehta said that inaction on the part of a Constitutional authority like the Governor was better addressed in the political sphere. The Supreme Court was not the only problem-solver in the country. Every problem cannot be resolved through a judicial order, he said.

The Solicitor General said the court should stick to its rule declared in the National Judicial Appointments Commission (NJAC) judgment that each organ of governance – the legislature, executive, and judiciary – must stick to its turf.

"We do not intend to micro-manage the government. We will never interfere. But suppose, if a particular function is entrusted to the Governor, and for years together he withholds a Bill, will that also be beyond the power of judicial review of this court... When this Court has in the past set aside the Constitutional Amendment | The Forty-second Constitutional

Suppose a constitutional functionary entrusted with certain functions refuses to discharge those functions without any valid reasons, are the hands of the constitutional courts tied? Are we powerless?

JUSTICE B.R. GAVAI Chief Justice of India

Amendment Act of 1976], which had limited the power of judicial review as a violation of the Basic Structure, can we say this court is now powerless?" CJI Gavai asked Mr. Mehta.

#### Constitutional powers

The Solicitor General responded that time limits may apply to statutory authorities like a District Collector, but not to Constitutional powers like the President and Governors. He said a Governor's position was sui generis, as they are appointed by the Union government but are also an integral part of the State legislature.

The law officer said there may be several reasons, at times political or democratic, for a Governor to delay assent to a State Bill. How could the Supreme Court step in and prescribe deadlines when none exist in the Constitution, he asked.

Justice P.S. Narasimha said State Bills would be left hanging in vacuum if no outer time limits were set for the Governor to grant assent.

"Though you cannot specify a time limit, but, at the same time, there should be some way by which the process [of assenting to Bills] works. Can it be a situation when it means 'full stop' if the Governor chooses to not act on a Bill... there is nothing further?" Justice Narasimha asked.

Mr. Mehta responded that only "two or three States" have come to the Supreme Court complaining of their Governors. There was no flood of litigation against Governors.

To this, Justice Surya Kant observed that Governors' decisions to act or 
not act varied from State to 
State. He asked whether 
the Centre was shutting off 
aggrieved States from approaching the court 
against gubernatorial 
inaction.

The Centre's law officer maintained that the judiciary cannot tie down the President and Governors to three-month timelines as done in the April 8 judgment.

"But if there is a wrong, there must be a remedy... This court is a custodian of the Constitution," the Chief Justice reacted. Mr. Mehta said each organ was a custodian of the Constitution in its own field.

Justice Narasimha said seeking a solution in the political sphere each time would result in a logjam.

The Solicitor replied that issues like delays in assenting to Bills were not solvable by the court. The solution lay in the political sphere where elected representatives were answerable to the people, at least every five years.

"But the Governor is not answerable to the people," the CJI pointed out.

#### 'Judicial restraint'

Referring to the April 8 judgment's direction that pending State Bills would be deemed as approved if the President and Governors did not act within the three-month deadline, Mr. Mehta said that restraint in the exercise of judicial power, especially when it concerned high Constitutional authorities, was a facet of the separation of powers, which was a part of the basic structure of the Constitution.

The Chief Justice said that while the Bench could quite appreciate the Centre's arguments against restricting Governors and the President to a "timebound programme" and the grant of 'deemed assent', it could not accept a situation in which the Governor merely sat for four years on State Bills.

"Then what happens to the democratic set-up of the government? What happens to the will of the two-third of the majority of the legislature of a particular State? We are on the question of a Governor, however high he may be, sitting on Bills passed by a competent legislature," Chief Justice Gavai observed.

The Solicitor's reply was illustrative. He asked if the President could step in and decide long-pending cases in the Supreme Court.

"It cannot be that every problem has a solution only at the doors of this court, and political and democratic solutions are not solutions," Mr. Mehta said, concluding his submissions for the Union government.



Concerning trend: Voters displaying identity cards while standing in queue to cast their votes at a polling booth for the last phase of the general elections, in Salmabad, Patna on June 1, 2024. ANI

# How women migrant electors are disenfranchised in the Bihar SIR process

The Election Commission which has highlighted the 'frequent migration of population from one place to another' as a justification for the 'intensive verification drive' fails to mention marriage, which is the most common ground for female migration in India

Prasenjit Bose

The story so far:

he enumeration phase of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar has excluded around 65 lakh electors from the draft electoral roll published on August 1, 2025.

#### What did data show?

The aggregated data published by the Election Commission of India (EC) revealed permanent migration as the predominant cause for the deletion of names from the electoral roll as on June 24, 2025, which was the base roll for the SIR exercise. Out of the 65 lakh total deletions, over 55% entries were categorised as permanently shifted or untraceable, around 34% as deceased, and only 10.8% as multiple enrolments (Table 1).

The publication of separate Assembly Constituency (AC)-wise lists of excluded or deleted electors, as directed by the Supreme Court, has made granular data analysis possible. The Hindu's Data Point analysis based on the top nine ACs in Bihar with the most deletions has revealed that 56% of the 4.73 lakh aggregate deletions in these ACs were female electors. Out of the 2.68 lakh female electors excluded from these nine ACs, 46% were deleted for having permanently shifted, 27% for being untraceable, 20% as deceased and only 6% as multiple enrolments. 66% of the 1.23 lakh female electors deleted for having permanently shifted were in the 18 to 39 years age cohort (Table 2).

#### What does the mass deletion of female migrant voters imply?

The disproportionate deletion of 'permanently shifted' female electors in the 18-39 age group points to the en masse exclusion of married women, given that Census data shows marriage to be the predominant cause of female migration – not only in Bihar but across India. 85.7% of female migrants in Bihar migrated due to marriage, as per latest available Census data (2011). These findings not only establish a built-in exclusionary bias against migrants in the very design of the

### Migrant women at a loss

The disproportionate deletion of 'permanently shifted' female electors in the 18–39 age group points to the en masse exclusion of married women, given that Census data shows marriage to be the predominant cause of female migration

Table 1: Key findings from the enumeration phase of Bihar SIR (June 24-July 25, 2025)

		[%]
Total electors (as on June 24, 2025)	7.89	100
Enumeration forms received (by July 25, 2025)	7.24	91.8
Enumeration form not submitted	0.65	8.2
	Total (in lakh)	(%)
Excluded from draft electoral roll	65	100
Permanently shifted/not found	36	55.4
Deceased	22	33.8
Enrolled at multiple places	7	10.8

Source: Election Commission of India, Press Note # ECI/PN/270/2025 dated 27.07.2025 Table 2: Findings of The Hindu's Data Point based

	Total	56
Total deletions	4,73,190	-
Excluded female electors	2,68,829	56.1%
Reason-wise exclus	ion among fema	le electors
Permanently shifted	1,23,825	46.1%
Untraceable	73,615	27,4%
Deceased	54,780	20.4%
Multiple enrolments	16,609	6.2%
Age-wise breakup o electors	f permanently s	hifted female
18-39 years	81,679	66%
40 & above	42,146	34%

Source: "Bihar SIR: Latest ECI data raises more questions over higher deletions among women", The Hindu, 20.08.2025

Bihar SIR 2025 process, but also a gender bias against female migrant electors, particularly young married women.

The eligibility criteria of a person to be registered in the electoral roll of a specific constituency is that they need to be "ordinarily resident" in said constituency as provided in the Representation of the People Act, 1950. However, the concept of "ordinary residence" has not been clearly defined anywhere in the statutes, leaving ample scope for arbitrary or erroneous deletions. The process followed under Bihar SIR, involving submission of a filled up enumeration form by existing electors within a 30 days window, has further added a new extra-legal criterion which is hostile towards migrants in general and migrant women in particular.

### Can such deletion lead to disenfranchisement?

It is notable that the EC's SIR order dated June 24, which highlights "frequent migration of population from one place to another on account of education, livelihood and other reasons" as a justification for the supposed "intensive verification drive to verify each person before enrolment as an elector" fails to even mention marriage, which is the most common ground for female migration in India. EC's SIR data clearly reveals that deletions on account of multiple enrolments are far less than the number of deletions on account of migration. Such deletions of permanently shifted electors, without at least ensuring their enrolment in their current place of residence amounts to disenfranchisement.

The EC's Manual on Electoral Rolls (March 2023, Document 10, Edition 2) states in Chapter 8 that, "Section 20 (7) of the Representation of the People Act, 1950 provides that the Electoral Registration Officer shall determine a question as to where a person is ordinary resident at any relevant time, with reference to all facts and to such rules as may be made by the Central Government in consultation with the Election Commission. The Central Government and the Election Commission have not made any rule on this subject till date."

The decision of the Election
Commission of India to initiate the SIR
process in Bihar — a State with the highest
inter-State out-migration rate in India as
well as a high level of intra-State migration
— without first addressing the legal and
procedural ambiguities surrounding the
status of migrant electors, especially
those migrating because of marriage, has
led to the en masse exclusion and
disenfranchisement of migrant electors.
The EC's unwarranted obsession with
"foreign illegal migrants" and citizenship
determination has deflected it from
addressing more relevant and critical
issues.

#### What is the way forward?

While resolving the larger question of how to legally determine "ordinary residence" for migrant electors in general and marriage-driven migration in particular may take some time, immediate steps are required to prevent the unjust en masse exclusion of migrant electors in Bihar. The EC's latest status update issued on August 21 reports that only 70,895 claims and objections and 2.28 lakh Form 6 applications (addition of new electors) have been filed till date. At this rate, a large bulk of 36 lakh electors deleted as permanently shifted or untraceable would remain excluded in the final electoral roll.

Extending the deadline for filing claims and objections by another 30 days, initiating a process of re-verification of the permanently shifted and untraceable categories, and ensuring mandatory re-enrolment of deleted migrant electors in their current constituency of residence may provide some relief. As far as female migrants are concerned, the decision to retain her name in the electoral roll of her natal household or be transferred to her marital household should rest with the female elector herself. It should not be imposed by the EC.

Prasenjit Bose is an economist and activist.

# Bills to oust arrested Ministers trigger chaos

Bills in focus | The three Bills tabled by the Home Minister propose the removal of Prime Minister, Chief Ministers and Ministers under certain conditions

Bill, 2025

1 Constitution (One

Hundred And Thirtieth

Amendment) BRL 2025

Conditions for removal:

Arrested and detained

serious criminal charges

for 30 consecutive days on

· Facing charges of

of five years

or more

offences punishable

with imprisonment

The Bills were referred to a Joint Committee of Parliament comprising 21 LS and 10 RS members

The Union government says the pieces of legislation are intended to bring 'morality back into politics'

2 Government of Union

Territories (Amendment)

Removal authority:

Union Ministers)

State Ministers)

Territories)

The President (for PM and

Governors (for CMs and

Lieutenant-Governors

(for Ministers in Union

Amit Shah and Venugopal engage in sharp exchange over the former's arrest in 2010

Sandeep Phukan Vijaita Singh

NEW DELHI

pposition and ruling party MPs exchanged barbs in the Lok Sabha on Wednesday over the government's claim of bringing in political morality through three new Bills allowing the removal of elected representatives arrested on serious criminal charges.

As the Bills were introduced, Union Home Minister Amit Shah and Congress leader Venugopal engaged in a sharp spat over Mr. Shah's 2010 arrest while he was Home Minister of Gujarat.

Congress Trinamool MPs escalated their protest by tearing copies of the proposed legislation in front of Mr. Shah's seat, resulting in a brief jostle between Opposition and rul-

party MPs. BJP members, including Union Ministers Kiren Rijiju and Ravneet Singh Bittu. stepped in to shield Mr. Shah, while the Trinamool accused the Ministers of "pushing and shoving" women MPs.

As the Home Minister introduced the three Bills, Opposition MPs shouted that they were "unconstitutional and anti-federal". A resolution was passed by a voice vote to refer them to a Joint Committee of Parliament that will have 21 members from the Lok Sabha and 10 from the Raiva Sabha. The Committee has been mandated to submit its report to the House by the Winter Session.

The three Bills are the Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025; the Constitution (One Hundred And Thirtieth Amendment) Bill.

2025; and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025. The Bills propose that any Prime Minister, Chief Ministers, or Ministers who are arrested and detained in custody for 30 consecutive days without obtaining bail, on charges of committing an offence punishable with imprisonment for five years or more, shall be removed from office by the

31st day. For example, the Prime Minister in this situation can be removed by the President, or a Chief Minister by the Governor of the State, if they do not resign on their own.

'Return to medieval era' Leader of Opposition in the Łok Sabha Rahul Gandhi, speaking at an event to felicitate the joint Opposition Vice-Presidential candidate, said the Bills would take the country back to "medieval times when the King could remove anybody at will".

3 Jammu and Kashmir

(Amendment) Bill, 2025

Additional

provision:

sllows for the

possibility of

reappointment

detained Minister

or Chief Minister

s released

Reorganisation

He explained how the proposed legislation could be used. "He tells ED to put a case and a democratically elected person is wiped out within 30 days," Mr. Gandhi said.

As soon as the Bills were tabled in the Lok Sabha at

2:00 p.m., the House witnessed uproarious scenes as Opposition members trooped into the well, raising slogans. Opposition MPs, including the AI-MIM's Asaduddin Owaisi and Congress MPs Manish Tewari and Mr. Venugopal. opposed the introduction of the Bills, saying that they were against the Constitution and federalism.

Political morality

"Leaders of the BIP are saying that this Bill is to bring morality into politics. Can I ask the Home Minister a question? When he was the Home Minister of Guiarat, he was arrested. Did he uphold morality at that time?" Mr. Venugopal asked.

Mr. Shah promptly responded by accusing the then-Congress government at the Centre of levelling false allegations.

"I want to set the record straight. Fake allegations were levelled against me. but despite that, I abided by morality and ethics and not only resigned but did not accept any constitutional post until I was cleared of all charges," the Home Minister said.

"The Constitution is being amended to turn this country into a police state," warned Mr. Owaisi.

"The Bill opens the door for political misuse," said Mr. Tewari.

Accusing the government of bringing the Bills in "undue haste", Revolutionary Socialist Party MP N.K. Premchandran said. "These Bills are not being introduced as per the procedures of the House... They have not even been circulated to members."

**RAHUL SLAMS BILLS** 

» PAGE 5

# Why India needs a national space law

What does the Outer Space Treaty of 1967 stipulate? Is it self-executing? Why is it important that countries enact their own national space legislations? What has been India's approach to space legislation? Why is creating affordable insurance frameworks for space startups crucial?

#### EXPLAINER

#### Shrawani Shagun

#### The story so far:

ndia is set to celebrate its second National Space Day on August 23. Following Chandrayaan-3's soft-landing near the lunar south pole to the upcoming Gaganyaan and Chandrayaan missions, as well as the Bharat Antariksh Station, the Indian space programme is set to make history many times over. Yet an essential component remains grounded – the legal architecture. In the race to explore, innovate, and commercialise outer space, a strong space law is necessary.

#### What about global space legislation?

The Outer Space Treaty of 1967 establishes that space is the province of all mankind, and therefore prohibits national appropriation, and places responsibility on states for national activities in space, whether conducted by the government or private entities. Its companion agreements create binding frameworks of rights, responsibilities, and liability rules. However, these treaties are not self-executing. According to Aarti Holla-Maini, director of the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), "The core United Nations treaties on outer space provide the foundational principles for all space activities: from the peaceful use of outer space to the responsibility and liability of states. National legislation is the means by which nations can give effect to these principles domestically, ensuring that their growing space sectors develop in a safe, sustainable, and internationally responsible way." India has ratified the key UN space treaties but it is still in the process of enacting comprehensive national space legislation.

While space policy may signal intent, law is what creates an enforceable structure. "National space legislation offers predictability, legal clarity, and a



The ISRO carrying out the Well Deck trials of the Gaganyaan missions's crew module in 2024. FILE PHOTO

stable regulatory environment for both government and private actors," Rossana Deim-Hoffmann, UNOOSA Global Space Law Project Lead said. Many countries now have national space legislation. Japan, Luxembourg, and the U.S. have enacted frameworks to facilitate licensing, liability coverage, and commercial rights over space activities.

#### Will India enact similar legislation?

India's approach to space legislation reflects a methodical, incremental strategy. As space law expert Ranjana Kaul notes, "It should be understood that national space legislation includes two cardinal interdependent aspects: (i) technical regulations governing space operations in orbit by commercial entities — this is the first aspect of 'authorisation' process under Article VI (of the Outer Space Treaty). The Department of Space is proceeding meticulously in this matter."

This methodical approach has yielded concrete regulatory developments, which includes the Catalogue of Indian Standards for Space Industry, critical for ensuring the safety of space operations; the Indian Space Policy, providing details of activities that non-governmental entities are encouraged to undertake; and the IN-SPACe Norms, Guidelines and Procedures (NPG) for implementation of Indian Space Policy, 2023, in respect of authorisation of space activities.

However, the second component is still pending. According to Dr. Kaul, "(ii) the overarching regulatory framework (textual part) – this is the ... 'space activities law' that will contain provisions of the OST that are meticulously, carefully, appropriately drafted."

#### What are industry perspectives?

From the industry's standpoint, the current regulatory transition creates significant operational challenges. Gp. Capt. T.H. Anand Rao (retd.), director of the Indian Space Association, identified priorities for national space legislation beginning with the fundamental need for a statutory authority. "IN-SPACe, which currently operates

without formal legal backing, requires clear statutory authority to strengthen its role as the central regulatory body." Mr. Rao said. "The national space law should clearly set out licensing rules. qualifications, application processes, timelines, fees, and reasons for acceptance or denial, to avoid unnecessary delays and confusion from multiple ministry approvals." The dual-use nature of space technologies creates particular complications, with companies facing delays from multiple ministry clearances even after provisional approvals. Clear FDI rules, such as allowing 100% FDI in satellite component manufacturing under automatic routes. would attract critical capital for startups to scale operations. This operational clarity extends to liability frameworks. with Mr. Rao emphasising that "while India is ultimately responsible internationally, private companies must hold proper third-party insurance to cover any damages. This includes creating affordable insurance frameworks for startups managing high-value space assets, Innovation protection remains equally crucial, "legislation should secure intellectual property rights without excessive government control, encourage partnerships among industry, academia, and government, and foster investor trust." This balanced approach would prevent migration of talent and technologies to more IP-friendly jurisdictions. Mr. Rao also stressed the need for mandatory accident investigation procedures, enforceable space debris management laws, unified frameworks for space-related data and satellite communications, and an independent appellate body to prevent conflicts of interest. Without statutory backing, IN-SPACe's decisions remain vulnerable to procedural challenges.

Shrawani Shagun is a researcher focusing on environmental sustainability and space governance.

#### THE GIST



The Outer Space Treaty of 1967 establishes that space is the province of all mankind, and therefore prohibits national appropriation, and places responsibility on states for national activities in space, whether conducted by government or private entities.



India's approach to space legislation reflects a methodical, incremental strategy.



Gp. Capt. T.H. Anand Rao (retd.), director of the Indian Space Association, identified priorities for national space legislation beginning with the fundamental need for a statutory authority.